प्रदेश में सोमवार को 282 ही नए करोना संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में भी थोड़ी और गिरावट के बाद 110 नए मरीज पाए गए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमण से और राहत मिली है। इस दौरान राज्य में केवल 282 ही नए संक्रमित मिले हैं। जबकि 11 सौ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस बीच प्रदेश भर में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में करोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। सोमवार को राज्य के 27 जिलों में 282 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 531 रोगी पाए गए थे। इधर आज राज्य के सात जिले अलवर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर और जैसलमेर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं राजधानी जयपुर में रविवार के मुकाबले 81 मामले कम मिलने साथ ही 110 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा में 28, जोधपुर में 20, नागौर में 14, उदयपुर में 12, भीलवाड़ा में 10, बारां, कोटा व बीकानेर में 9-9, बाड़मेर में 7, गंगानगर, सवाई माधोपुर व झुंझुनूं में 6-6, अजमेर, सिरोही व करौली में 5-5, पाली में 4, दौसा, सीकर, टोंक व झालावाड़ में 3-3, चूरू, जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद तथा हनुमानगढ़ में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 1116 और मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 98.93 फीसदी पर पहुंच गई है। उधर एक्टिव केस भी घटकर 4135 रह गए हैं। इनमें 1530 रोगी जयपुर जिले में हैं। जबकि अन्य जिलों में इनकी संख्या तीन सौ से भी कम है।

- **राज्य के सात जिले अलवर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर और जैसलमेर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।**
- **प्रदेश में सोमवार को 11 सौ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस बीमारी से कोई भी मौत नहीं हुई है।**

मानसरोवर व जगतपुरा में 9-9 नए संक्रमित

जयपुर जिले में सोमवार को 36 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 9-9 मरीज जगतपुरा और मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा मालवीय नगर व सांगानेर में 6, आदर्श नगर, सिविल लाइन, प्रताप नगर और टोंक रोड इलाके में 5-5 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच यहां 207 मरीज रिकवर हुए है।

युवाओं के समुचित विकास के प्रयास किए जाएंगे : लांबा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि राज्य की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए युवाओं की अपेक्षाएं अलग- अलग हैं, ऐसे में हर तबके के युवाओं के समुचित विकास के प्रयास किए जाएंगे।

लांबा ने यह बात सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के मीटिंग हॉल में राजस्थान युवा बोर्ड की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राज्य में युवाओं के विकास के लिए विभिन्न तरह के नवाचार किए जाएं। लांबा ने कहा कि उनका युवाओं के साथ कार्य करने का अनुभव रहा है ऐसे में युवाओं को सही दिशा में लाने तथा युवाओं का सशक्त करने के लिए बोर्ड विभिन्न तरह के कार्य सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने राज्य युवा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि नवीन राज्य युवा नीति का प्रस्ताव, राजीव गांधी युवा पुरुस्कार, यूथ एक्सीलेंस सेन्टर, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना सहित विभिन्न माध्यमों से युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में युवाओं के लिए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, सामाजिक समरसता सोच कार्यशाला, युवा स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको प्रोत्साहन संबंधी कार्य भी किये जाएंगे।

यूक्रेन से राजस्थानियों की वापसी के लिये भाजपा की हैल्पलाइन शुरू

यूक्रेन में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों एवं विद्यार्थियों की स्वदेश वापसी में सहायता उपलब्ध कराने के लिए भाजपा राजस्थान की हैल्पलाइन का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने शुभारंभ किया।

जयपुर। यूक्रेन में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों एवं विद्यार्थियों की स्वदेश वापसी में सहायता उपलब्ध कराने के लिए भाजपा राजस्थान की हेल्पलाइन का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से भाजपा राजस्थान की टीम हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। भाजपा हेल्पलाइन के नम्बर 8929208080 पर मदद के लिए विद्यार्थी और प्रवासी राजस्थानी कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन के शुभारंभ के मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान, प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक राजेन्द्र सिंह शेखावत, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक नवनीत सिंह राजपुरोहित इत्यादि उपस्थित रहे। डॉ. पूनियां ने हेल्पलाइन शुभारंभ के अवसर पर कहा कि, केन्द्र की मोदी सरकार यूक्रेन से प्रवासी भारतीयों व प्रवासी राजस्थानियों की स्वदेश वापसी के लिए मिशन गंगा के माध्यम से लगातार प्रयासरत है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

- **मिशन गंगा के माध्यम से मोदी सरकार भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए कर रही शानदार प्रयास, करोनाकाल में भी वंदे भारत मिशन की दुनियाभर में हुई प्रशंसा : डॉ. पूनिया**

उन्होंने कहा कि, यूक्रेन से भारतीयों की सकुशल वापसी हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर रोमानिया, पोलैण्ड और टोक्यो सहित वहां के बॉर्डर्स पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतियाराज सिंधिया, किरण रिजूजू, जनरल वीके सिंह को इस विशेष अभियान में जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। कई फ्लाइटस स्वदेश आ चुकी हैं और अन्य फ्लाइटस भी चरणबद्ध तरीके से भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचेंगी। भाजपा राजस्थान इकाई ने यह तय किया है कि यूक्रेन में हजारों की संख्या में राजस्थानी लोग व विद्यार्थी रह रहे हैं जिनकी स्वदेश वापसी में सहायता हेतु हेल्पलाइन शुरू की गई है।

प्रदेश नेतृत्व ने इस हेल्पलाइन नम्बर के कॉर्डिनेशन की जिम्मेदारी सुनील कोठारी, राजेन्द्र सिंह शेखावत, पंकज जोशी और हिमांशु शर्मा को दी है, जिनके साथ टीम में नवनीत राजपुरोहित, हिरेन्द्र कौशिक, अभिषेक आचार्य, राज बहादुर सिंह, जिनेंद्र शास्त्री, कविराज सेठी, शुभम प्रियदर्शी, मनोज शर्मा, शालिनी शर्मा, अनुराग तोतुका, पल्लवी शर्मा, रजनी सिंह, निकिता शेखावत, श्रवण शर्मा वाटिका इत्यादि हेल्पलाइन पर उपलब्ध देंगे।

वन स्टॉप शॉप प्रणाली के लिये बैठक

जयपुर। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा वन स्टॉप शॉप प्रणाली की 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागों को निर्देश दिए गए कि आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए ताकि निवेशकों को बाधा रहित सुविधाएं प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री का आभार जताया

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के प्रतिनिधिमण्डलों ने मुलाकात की तथा प्रदेश को ऐतिहासिक बजट देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी संघों से जुड़े कार्मिक भी इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा पर भरपूर खुशी का इजहार करते हुए मालाएं पहनाकर तथा साफे बांधकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़, हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानूखान बुधवाली, विधायक राजकुमार शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

भारतीय नागरिकों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सकुशल एवं सुरक्षित वापसी के लिए हों प्रयास : सीएम

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं की वहां से सुरक्षित एवं शीघ्र निकासी के लिये यूक्रेन, रूस, पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया की सरकारों से बात की जाए। उन्होंने कहा कि इन देशों में स्थित दूतावासों के माध्यम से भारतीय छात्र-छात्राओं से निरंतर सम्पर्क स्थापित किया जाए, ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि वे सकुशल एवं सुरक्षित वतन लौटेंगे।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। कीव और खारकीव में रह रहे कुछ भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं से उनकी स्वयं वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई। इस दौरान वहां की परिस्थितियों की जानकारी ली एवं उनकी हौंसला अफजाई करते हुए सकुशल वतन वापसी की दिशा में हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि यूक्रेन में युद्ध की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार भारतीय दूतावासों के माध्यम से वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्रयास कर रही है। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं।

सेना भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सेना भर्ती रैलियों के शीघ्र आयोजन के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। गहलोत ने पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सेना में भर्ती के लिए विगत करीब 2 वर्ष से रैलियों का नियमित आयोजन नहीं किया जा सका है। इसके चलते हजारों नवयुवक भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं और सशस्त्र सेनाओं में भर्ती का उनका सपना टूट रहा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती रैलियों में इन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का भी केन्द्रीय रक्षा मंत्री से आग्रह किया है।

गहलोत ने पत्र में बताया कि राज्य में वर्तमान में कोविड महामारी के कारण भर्ती रैलियां नहीं हो रही हैं। वर्ष 2021 में उदयपुर, जयपुर तथा अजमेर में तीन भर्ती रैलियां जरूर हुई थीं, लेकिन उनकी लिखित परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी हैं। गहलोत ने प्राप्त आंकड़ों का पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सेना में भर्ती के लिए वर्ष 2015-16 में 127, वर्ष 2016-17 में 102, वर्ष 2017-18 में 106, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 92-92 रैलियां आयोजित की गईं, लेकिन बीते करीब 2 वर्षों से इनका नियमित आयोजन नहीं होने से हजारों नवयुवक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वे भर्ती रैलियों के शीघ्र आयोजन तथा अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान करने के लिए भर्ती निदेशालय (सेना मुख्यालय) को निर्देश दें, ताकि सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त होकर राष्ट्र सेवा करने का प्रदेश के नवयुवकों का सपना साकार हो सके।

'गर्भवती अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त नहीं करें'

जयपुर। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में गर्भवती अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसकी पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग में एक पद रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अनिता कुमावत की याचिका पर दिए। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता को एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 14 फरवरी को बुलाया था जबकि याचिकाकर्ता गर्भावस्था के कारण मौजूदा समय में शारीरिक दक्षता परीक्षा देने में असमर्थ है।

डिस्कॉम पर 11.25 लाख का हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अलवर स्थित खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए उस पर 11 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश दीपा देवी व अन्य के दावे पर दिए। दावे में कहा गया कि रतिराम मीणा कठूमर के बैरका गांव स्थित अपने खेत में 26 जनवरी, 2018 को पानी दे रहा था।

जमीन पर रखे डीपी से अचानक करंट फैलने से रतिराम को करंट लग गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विधान सभा सचिवालय में कार्यरत पूरण मल महावर, सहायक सचिव को आज अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह में विभिन्न संघों द्वारा विदाई दी गई। विधानसभा के वरिष्ठ उप सचिव महेश चन्द्र शर्मा ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। विधान सभा सचिवालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की ओर से अधिकारी को बचत का चेक प्रदान किया। समारोह का संचालन दुर्गादास मूलचंदानी ने किया।

जयसिंहपुरा खोर में 9वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म, मामला दर्ज

जयपुर (कासं)। शहर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में 9वीं क्लास की छात्रा के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की मां रोते हुए थाने पहुंची और बोली- मेरी बेटी को बचा लो। कुछ लोग उसे कॉल गर्ल बनाना चाहते हैं। पुलिस ने मामले में महिला और युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने जब खुद पर आप बीती पुलिस के साथ साझा की तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी में जुट गई है।

जयसिंहपुरा खोर पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली 15 साल कि किशोरी की मां ने घर के पास ही रहने वाले गौरव और ममता के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। पीड़ित के साथ सितंबर में गौरव नाम के युवक ने रेप किया था, जो कॉलेज में पढ़ता है। इस दौरान उसे बिना बताए वीडियो बना लिए। इस बारे में जब पीड़िता ने अपनी मां को बताया तो बदनामी के डर से चुप हो गई। कुछ दिनों के लिए बेटी का घर से बाहर आना-जाना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को फोन कर वापस बुलाना शुरू कर दिया। उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़िता को वीडियो भेजे तो घर में कोहराम मच गया। मां ने आरोपी के खूब हाथ-पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं माना। इस बीच ममता नाम की एक महिला भी आरोपी के साथ जुड़ गई। दोनों ने किशोरी को कहा कि उसे जहां भेजें, वहां पर जाना होगा। नहीं गई तो उसके वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में डाल देंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। पीड़िता की मां ने फिर से आरोपी के हाथ-पैर जोड़े कि वीडियो डिलिट कर दें, लेकिन आरोपी नहीं माने। आखिरकार पीड़िता अपनी मां के साथ रोते हुए रविवार को थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रेप, पोक्सो, ब्लैकमेलिंग समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है।

इसी प्रकार जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में ही एक और किशोरी के साथ हैवानियत की गई। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली पंद्रह वर्षीय एक किशोरी के बारे में उसकी चाची ने केस दर्ज कराया है। परिवार के जानकार एक डॉक्टर पर केस दर्ज कराया है कि वह किशोरी को जबरन कार में अपहरण कर ले गया। तीन घंटे कार में ही अश्लीलता की हदें पार कीं और उसके बाद किसी को भी बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

ग्रेटर निगम और बीवीजी कंपनी की खींचतान और हड़ताल के बीच फंसी जयपुर की सफाई व्यवस्था

जयपुर (कासं)। स्वच्छता सर्वेक्षण आज से शुरू होगा, लेकिन जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था ग्रेटर निगम और बीवीजी कंपनी की खींचतान के बीच फंसकर रह गई है। बीते 6 दिन से घर-घर कचरा संग्रहण बंद होने के कारण मुख्य सड़कों से लेकर अंदरुनी गलियों तक गंदगी के ढेर लगे पड़े है। हूपर संचालकों की हड़ताल फिलहाल टूटने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे है। इसके बावजूद भी निगम आयुक्त से लेकर स्वास्थ्य उपायुक्त जैसे जिम्मेदार अफसर बेपरवाह बने बैठे है। इसी बीच अब उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने बीवीजी कंपनी को कार्यमुक्त करके सफाई व्यवस्था की ठोस कार्य योजना बनाने के लिए नोटशीट लिखी है।

जानकारी के मुताबिक बीवीजी कंपनी ने ग्रेटर निगम पर 14 करोड़ रु. का बकाया भुगतान निकाला है। समय पर ग्रेटर निगम से भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी ने कचरा उठाने वाले हूपर संचालकों को पैसा नहीं दिया। इस कारण सभी हूपर संचालक हड़ताल पर चले गये और

- **उपमहापौर ने निगम आयुक्त को नोटशीट लिखकर बीवीजी कंपनी को हटाने की मांग उठाई**

बीते 6 दिन से शहर में घर-घर कचरा संग्रहण बंद पड़ा है। हालांकि निगम प्रशासन खुद के संसाधनों से कचरा उठवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह नाकाफी है। इसी बीच 1 मार्च से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, केन्द्रीय टीमें कभी भी यहां आकर सफाई जांच सकती है। हालात बदत्तर होने के बावजूद भी ग्रेटर निगम के अफसर जयपुर की अच्छी रैंकिंग लाने का दावा करने से नहीं चूक रहे है, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी कैसे ?

उधर महापौर सौम्या गुर्जर लगातार शहर का दौरा करके सफाई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन वाहनों के अभाव में सफाई कर्मचारियों की मेहनत भी फेल होती दिख रही है। चर्चा है कि महापौर सौम्या गुर्जर-आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के बीच की खींचतान का खामियाजा भी जयपुर के लोगों को उठाना पड़ रहा हैं। इसी बीच सोमवार को उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने जयपुर में लगातार बिगड़ती सफाई-सीवरेज व्यवस्था पर चिंता जताते हुए निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को नोटशीट लिखी है। कर्णावट ने कहा कि जयपुर की सफाई व्यवस्था को बंटाधार करने वाली बीवीजी कंपनी को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निगम स्वयं के संसाधनों व अन्य उपायों से वैकल्पिक इंतजाम करे। कर्णावट ने सवाल उठाया है कि टैंडर की शर्तों की खुलेआम धज्जियां उडा रही बीवीजी कंपनी पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। जबकि करीब सवा साल पहले 28 जनवरी 2021 को हुई बोर्ड मीटिंग में बीवीजी का करार रद्द करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद अब कोर्ट का स्टे भी हट चुका है।

जेवीवीएनएल ने पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन दिलवाने की अर्जी वापस लेने की मंजूरी मांगी

जयपुर, (का.सं.)। शहर की पृथ्वीराज नगर योजना में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटवाने से जुड़े मामले में जेवीवीएनएल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में दायर अर्जी को वापस लेने का आग्रह किया है। हालांकि यह प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर नहीं आया है। जेवीवीएनएल ने पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश कर बिजली कनेक्शन जारी करने की अनुमति मांगी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि उनकी पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने की क्या मंशा है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि पीआरएन में अनियमित कॉलोनियों के मकानों में अदालत ने ही बिजली कनेक्शन जारी करने पर पाबंदी लगा रखी है। राज्य सरकार अदालती आदेश से बंधी हुई है। ऐसे में यदि अदालत की मंजूरी के बिना बिजली कनेक्शन लगाने की अनुमति देती है तो यह अदालती आदेश की अवमानना होगी। राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस अशोक गौड ने यह आदेश लोकेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने या नहीं देने के संबंध में उनकी क्या मंशा है। दरअसल याचिकाओं में कहा है कि राजस्थान बिजली एक्ट की धारा 43 के तहत प्रार्थियों को बिजली कनेक्शन दिया जाए। यह उनका अधिकार है व इसे रोका नहीं जा सकता। यदि सरकार ने यदि प्रदेश में कहीं पर भी अतिक्रमियों को बिजली नहीं देने का निर्णय ले रखा है तो इस संबंध में परिपत्र जारी करे। प्रार्थियों के सोसायटी पट्टे होने के कारण वे बिजली कनेक्शन सहित अन्य सुविधाओं से वंचित हैं।

महिला के गले से चेन लूटी

जयपुर। आदर्श नगर थाना इलाके में स्कूटी सवार लुटेरे एक महिला की चेन लूट ले गए। पुलिस ने बताया गुरुनानकपुरा निवासी रोहित अग्रवाल की पत्नी 27 फरवरी की दोपहर शंकर समोसे वाले से पहली गली में घर की तरफ जा रही थी।

ठेकेदार ने किया महिला से दुष्कर्म

जयपुर (कासं)। करणी विहार थाने में एक महिला मजदूर ने ठेकेदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार मूलतया दूदू निवासी 30 वर्षीया महिला इलाके में किराए से कमरा लेकर परिवार के साथ रहती है। वह अपने परिवार के साथ ही मजदूरी करती है।

सिर्फ राजस्थान रोडवेज को यू.डी.टैक्स चुकाने के नोटिस थमाये, जयपुर मेट्रो और जेसीटीएसएल पर चुप्पी क्यों?

आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वायत्त शासन सचिव को पत्र लिखकर सवाल उठाया

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) चुकाने को लेकर रोडवेज प्रबंधन और नगरीय निकायों के बीच अब तनातनी की नौबत आ गई है।

आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वायत्त शासन सचिव को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि हर रोज 8 लाख यात्रियों को बेहद कम कीमत पर सफर करवाने वाले रोडवेज विभाग को तो यूडी टैक्स वसूली के नोटिस जारी हो रहे हैं, जबकि मात्र 20 हजार लोगों को सफर करवाने वाली जयपुर मेट्रो और जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जेसीटीएसएल से यह वसूली क्यों नहीं होती। उन्होंने राजस्थान रोडवेज को इस टैक्स से मुक्त करने तथा स्थानीय निकायों से रोडवेज को बकाया 95.80 करोड़ रु. दिलाने की मांग भी उठाई है।

- **रोडवेज के 95.80 करोड़ रु.स्थानीय निकायों पर बकाया है, यह रकम चुकता करे विभाग : भाटी**

एसोसिएशन के महासचिव सुधीर भाटी ने अपने पत्र में लिखा कि जयपुर शहर में जेसीटीएसएल के दो डिपो हैं, इसी तरह कोटा बस सर्विस लि. तथा उदयपुर बस सर्विस लिमिटेड से भी नगरीय विकास कर की वसूली नहीं की जाती।

इसके बावजूद राजस्थान रोडवेज के बस अड्डों पर नगरीय निकायों की टीमें यूडी टैक्स वसूली के लिए कुर्की करने पहुंच रही है। ऐसे में यह रोडवेज प्रबंधन के साथ द्वेषतापूर्ण नीति को दर्शाता है। इसलिए मांग है कि राजस्थान रोडवेज को इस टैक्स वसूली से मुक्त किया जाये।

भाटी ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 वर्ष पहले आरटीआईडीएफ फंड का अनुपात 75:25 के बजाय 50:50 करने का निर्णय हुआ था, वह भी आज तक लागू नहीं हुआ। इसके अलावा जयपुर में आगरा रोड पर रोडवेज विभाग ने नगर निगम जयपुर को अंबेडकर भवन बनाने के लिए जमीन दी थी, जिसके बकाया 65.80 करोड़ रु. आज तक नहीं मिले। जयपुर सिटी बस सर्विसेज लि. के संचालन व सांगानेर व विद्याधर नगर डिपो के बकाया लीज राशि के करीब 30 करोड़ रुपये भी रोडवेज प्रबंधन को आज तक नहीं चुकाये गये, उल्टा यूडी टैक्स के नोटिस थमाकर रोडवेज की साख को प्रभावित किया जा रहा है। रोडवेज पर जितना टैक्स सभी नगरीय निकायों का बकाया है, उससे करीब 25 गुणा ज्यादा रकम तो रोडवेज प्रबंधन स्वायत्त शासन विभाग की अधीनस्थ स्थानीय निकायों से मांगता है।